

are closed, known as sick mills. As for the other, I do not have information at the moment. I will look into it.

श्री एस० एम० जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब कभी कोई बड़ी मिल बन्द हो जाती है और उस को लेने के लिये मजदूरों की तरफ से दरखवास्त आती है और अगर कोई क्रेडिटर कोर्ट में जाकर लिक्विडेशन प्रोसीडिगज शुरू कर देता है तो हम को कड़ा जाता है कि जब तक प्रोसीडिगज खत्म नहीं हो जाती, तब तक मिल को नहीं ले सकते हैं। जैसे बम्बई की एडवर्ड मिल बहुत दिनों से बन्द थी, उस का मामला कोर्ट में पड़ा है, हम लिये हम उस को ले नहीं सकते हैं। क्या सरकार इस के बारे में सोचने की कोशिश करेगी कि क्योंकि जब आप लेने की कोशिश करेंगे तभी कोई आदमी, क्रेडिटर, कोर्ट में जा सकता है और फिर जो हमारी नीति है उसको हम अमल में नहीं ला सकते हैं—इसलिए क्या सरकार कोई कानून लाने या अन्य प्रबन्ध करने की बात सोच रही है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी भी जो प्रोसीजर है उसकी मातहत किसी मिल को लेने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। अगर कोई क्रेडिटर इस तरह से रुकावट डालने की बात करता है, कोर्ट में जाता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट या केन्द्रीय सरकार की ओर से अगर कोई कार्यवाही होगी भी तो वह कानूनी कार्यवाही ही होगी, उसके लिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप कानपुर की न्यू विक्टोरिया मिल के बारे में भी बताइये जिसको कि आपने पहले लेने के लिए तय किया था लेकिन अभी तक नहीं लिया है।

श्री ब० रा० भगत : उसको हम देखेंगे।

SHORT NOTICE QUESTION

Gherao of General Manager of South Eastern Railway

+

SNQ. 10. SHRI KANWAR LAL GUPTA :
SHRI NARAIN SWARUP
SHARMA :
SHRI SHRI CHAND GOYAL :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Manager of the South Eastern Railway was gheraoed by some railway employees along with a Member of Parliament; and

(b) the steps Government propose to take to check such incidents ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R. L. CHATURVEDI) : (a) Yes, Sir.

(b) Since this is a law and order matter, we brought it to the notice of the concerned State Government

श्री कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, सरकार को एक माडल एम्प्लायर बनना चाहिए, उसके अन्तर्गत जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मुविधायें देनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में वे हड़ताल भी कर सकते हैं, यह उनका हक है लेकिन जहाँतक घेराव की बात है, हम उसको ऐन्टीनेशनल समझते हैं और उसको पूरी तरह से कन्डेम करना चाहते हैं क्योंकि इससे देश में एनाकी और लालेसनेस पैदा होती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोर्ट ने जब फैसला कर दिया कि घेराव कानून के खिलाफ है तो पुलिस को इस घेराव के सम्बन्ध में कब खबर की गई और पुलिस ने अभीतक क्या कार्यवाही की है ? और आपने डिपार्टमेंटल क्या कार्यवाही की है ? क्या पिछले दो तीन महीनों में इस प्रकार के घेराव और भी हुए हैं ? यदि हाँ, तो उनका व्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): पुलिस को 18 मार्च को खबर की गई। अभी कोई कार्यवाही शायद नहीं हुई है लेकिन इसकी इत्तला मुख्य मन्त्री और उप मुख्य मन्त्री को 17 मार्च को ही मैंने दी थी और उन्होंने इस घेराव को दूर कराने का कदम उठाया जोकि स्वागत योग्य है।

श्री कंबर लाल गुप्त: आपने डिपार्टमेंटल कार्यवाही की और क्या ऐसे घेरे हुए और हैं?

डा० राम सुभग सिंह: एक घेराव हुआ अदरा में 24 फरवरी को, यह हुआ 17 मार्च को और एक हुआ 19 मार्च को मोजपुर स्टेशन, साउथ ईस्टर्न रेलवे में।

श्री कंबर लाल गुप्त: अगर रेलवे में या सरकार के जो और कारखाने हैं वहां पर कल को पुलिस को बुलाया जाता है घेराव के समय, और अगर पुलिस नहीं आती है, कोई मदद नहीं करती है तो फिर उस समय सरकार के वे आहिसर्स डिमारलाइज न हों और उनकी रक्षा की जाये-क्योंकि वे आपके कहने के अनुसार काम कर रहे हैं— इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? क्या आपने इस समस्या को हल करने के सम्बन्ध में बंगाल गवर्नमेंट से कोई बात-चीत की है? यदि हां, तो क्या?

डा० राम सुभग सिंह: मैं ने पहले ही बताया कि मुख्य मन्त्री और उप-मुख्य मन्त्री को जब मैं ने इत्तला दी तो दोनों ने कहा कि हम इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने श्री विश्वनाथ मुकर्जी को वहां पर भेजा जिन्होंने वहां पर जाकर काफी प्रयास किया और मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मन्त्री दोनों ने स्वयं जनरल मैनेजर को टेलीफोन किया। उन लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप घेराव हटा।

जहांतक डिमारलाइज होने की बात है,

हम किसी भी रेल कर्मचारी को डिमार लाइज नहीं होने देंगे।

श्री कंबर लाल गुप्त: क्या कदम उठाया, यह तो बताया ही नहीं? अगर पुलिस नहीं आ: तो आप क्या करेंगे?

डा० राम सुभग सिंह: इस सिलसिले में मिनिस्टर को भेजा, वह गये, स्पीच दी और लोगों को हटाया।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मरकारी कर्मचारी घेराव के लिए मजबूर होते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जिसको टाला नहीं जा सकता है... (व्यवधान)... कोई न कोई असंतोष उनके मन में होता है जिसकी वजह से यह बात समय समय पर होती रहती है। सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की जो नीति चल रही है वह पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितने टेम्पोरेरी कर्मचारी निकाले गए थे उनमें से कितने वापिस लिए गए हैं और बाकी कब तक वापिस लिए जायेंगे? अगर उनको वापिस लेने का आपका प्लान नहीं है, और वे कर्मचारी अपना असंतोष व्यक्त करते हैं तो फिर इस प्रकार से उनके घेरावों को कन्डेम करके हम सफल नहीं हो सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह: जहां जहां घेराव हुए वहां वहां पर घेराव को उल्टेजना देनेवाले गैर-सरकारी थे, कुछ सरकारी कर्मचारी भी उसमें हो सकते हैं....

श्री नारायण स्वरूप शर्मा: इसका मूल-कारण क्या है?

डा० राम सुभग सिंह: मूल कारण के बारे में श्रु मन्त्री जी ने गवर्नमेंट की राय को यहां पर घोषित किया है और उसी के अनुकूल हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। हमारी सारी कार्यवाही उसी के अनुकूल होगी।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा : टेम्पोरेरी कर्मचारी जो निकाले गए थे उनमें से कितने वापिस लिए गए और बाकी कब तक वापिस लिए जायेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : 17 तारीख को आदेश मिला, हम इमीडिएटली कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने यह बेराव किया है उनकी संख्या कितनी थी ? और क्या ये वही सरकारी कर्मचारी नहीं हैं जिनके विरुद्ध यहां भारत सरकार ने निर्णय किया है, गृह मंत्रालय ने, कि उनके विरुद्ध प्रागे कैसे ज नहीं चलेंगे लेकिन अभी तक वहां उसके ऊपर अमल नहीं हुआ और इसी कारण उनको कदम उठाना पड़ा ? इसके अतिरिक्त कितनी देर उन्होंने जनरल मैनेजर को हिरामत में रखा, इसके बारे में भी जानकारी दें ?

डा० राम सुभग सिंह : लोगों ने जनरल मैनेजर को गार्डन रीच में 6 घंटे 12 मिनट तक हिरामत में रखा। जैसा कि मैंने पहले बताया उतोजित करने वाले गैर-सरकारी थे और यही नहीं कि गृह मंत्रालय के अन्तर्गत जो आते हो वही हों क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश रेल मंत्रालय को 17 मार्च को मिला और 17 मार्च को ही यह बेराव हुआ, दूसरा बेराव 24 फरवरी को हो चुका था। तीसरा बेराव 19 मार्च को हुआ। इस लिए माननीय सदस्य जो कहते हैं वह पूरी तरह से सही नहीं है। इस बेराव को हम गलत मानते हैं और इसको प्रश्न्य कमी भी नहीं देंगे।

श्री बूटा सिंह : ऐसा मालूम हुआ है कि यह बेराव हुआ उसमें, जिस संसद सदस्य का नाम आया है वे जनरल मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। तो ये जो बेराव हो रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के इनमें वह मुलाजिम नहीं बल्कि राजनीतिक

दलों के जो नेता हैं वही हैं ... (व्यवधान) ... मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन बेरावों को रोकने के लिए, यदि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारें पूरा कोआपरेशन नहीं देती हैं, तो केन्द्रीय सरकार क्या करना चाहती है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि सदन को विदित है गार्डन रीच में साउथ ईस्टर्न रेलवे के दफ्तर में 6 हजार कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर कोई एक माननीय सदस्य सवा सी आदमियों के साथ जनरल मैनेजर के कमरे में घुसे जो कि एक बिल्कुल निम्ननीय कार्यवाही थी जिसकी किमी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। — (व्यवधान) ... उन 6 हजार कर्मचारियों में से करीब करीब सारे के सारे दफ्तर में रहे और उनकी उत्तेजना में नहीं फसे।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य का नाम तो बताइये।

डा० राम सुभग सिंह : नाम तो छप चुका है श्री जे० एम० विस्वास।

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, generally the railway workers or any worker used to demonstrate for the ventilation of their grievances before the new form of demonstration, that is, gherao, came in. So, I would like to know whether it is a fact that the General Manager, South-eastern Railway, did not assure the deputationists who met him repeatedly- the delegation headed by the President of the South-eastern Railway Union and others, that he would sympathetically consider the cases of victimisation arising out of the strike of the 19th September, 1968 or otherwise, including the case of the casual workers who had served there for years together, who were declared as surplus and discharged ? They were casual workers and they were discharged straightaway. Even after the issue of the Home Ministry's orders in October, 1968, 7th January 1969 and the recent one, they were not taken back. May I know whether this demonstration was a manifestation of their hunger and anger and if so, what steps

are being taken to see that the orders are implemented without any delay ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: Sir, you were yourself present when during the reply to the general discussion on the railway budget, I categorically stated that there would not be any victimisation of any railway employec. I am prepared to review it, each and every case, if there is any victimisation. But in the face of that declaration, if any body wants to gherao the General Manager, that can never be allowed to happen on the railways. I repeat, if there is any victimisation, I am prepared to examine it.

SHRI KARTIK ORAON: There appears to be a mass hysteria for gheraos and it is a very serious situation that this tendency should be encouraged. I would like to know the name of that dignified Member of Parliament by whose actions commissions, omissions and initiative- the General Manager was gheraoed and the reasons thereof, for which the Government should be held responsible.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I quite sympathise with the hon. member.

MR. SPEAKER: He never gheraoed any body.

DR. RAMSUBHAG SINGH: Our officers on three occasions were put to great difficulty and I hope this type of gheraos would not occur in future, because this is objectionable.

SHRI SAMAR GUHA: Gherao is a general phenomenon linked with certain vital interests of labour. *(Interruption).*

MR. SPEAKER: What a pity, members behave like this.

SHRI SAMAR GUHA: Gheroa is a general pheonomemon of a deeper malady relating to the vital interests of workers and also the relation between employers and employees. In view of this, the West Bengal Government has taken a very bold step in evolving a new system in Durgapur industrial complex, particularly in concerns run by

the West Bengal Government, whereby the representatives of trade unions have been taken in the Board of Directors. This is a very bold step. In view of this, would the Government consider whether it is possible to set up a board of managment in all the railways, where the representatives of of the trade unions there would also be invited not only as participants but as members of the board, so that they may have an understanding of the problems, have a sobering effect and deal with the fundamental problems like ghereo fundamentally ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: As the House knows, the Government of India, long time back, not recently, enunciated its policy of worker's participation in management. The Government of India has got its own policy. We do not want to imitate others.

SHRI NARARENDERA KUMAR SLAVE: In the reply given by the minister is implicit a clear indication that the 125 men who participated in the gerao were instigated by political parties with political motives. It is necessary some-how or other to draw a line beyond with indiscipline and lawlessness, from our own employees must not be tolerated. He has himself condemned gheraos in no uncertain terms. May I know whether he will take bold step and suspend all those 125 workers ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: I have already replied how we propose to function under the directions issued by the Home Ministry. But anybody who wants willfully to contravene the rules will have to be firmly dealt with.

श्री प्रकाशवीर शास्त्रा: मैं यह जानना चाहता हूँ, जैसा अभी रेलवे मंत्री महोदय ने कहा कि जिन कर्मचारियों का या अधिकारियों का इस प्रकार घेराव होगा उन को सरकार की ओर से समुचित संरक्षण प्राप्त होगा। परन्तु यदि उन राज्यों की राज्य सरकारें शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ हों और अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन कर रही हों तो ऐसी स्थिति में कैसे आप उन को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, उन के सम्बन्ध

क्या आप के मस्तिष्क में कोई स्पष्ट नीति है ?
है तो, वह क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : अगर किसी रेल कर्मचारी पर ज्यादाती होगी तो उस को मैं अपने ऊपर ज्यादाती समझूंगा । चाहे वह कर्मचारी जनरल मंनेजर हो या कोई छोटा कर्मचारी हो, उस की रक्षा करने का प्रयत्न करूंगा ।

जहां तक वेस्ट बंगाल के मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री और मिर्चाई मंत्री का सवाल है उन लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है, उन के लिये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ।

SHRI K. P. SINGH DEO: Sir I, have had occasion to attend the South-Eastern Zonal Railway Users' Consultative Committee meetings where my hon. friends Shri Kartik Oraon is a member and Shri Biswas is also a member. In some of the meetings they pointed out that whenever we members say something the authorities are impatient to give us a patient hearing. So I am not surprised that some of the workers of the South-Eastern Railway had to resort to intimidating these officers. I want to know for how long these grievances have been brought to the notice of the Manager, South-Eastern Railway and why was it necessary for them to go in a body and meet him ? May I also know what is the definition of 'gherao', whether he was gheraoed and whether he was allowed to go into the room ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: That is an argument which, I think, if the hon. Member knew the reality he would not have advanced, because here there is no difficulty for any Member to tell me what he likes me to do. Even the persons who are involved have written to me. I am not a person who takes unduly long time to deal with letters. If somebody wants to indulge in any wrong action and even then you want to plead his case, that is not going to find any sympathetic attention.

श्री सु०प्र० सां: मुल्क में घेराव की बढ़ती हुई

कार्यवाहियों की वजह से जो मुल्क की प्रोपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है, इस की रोशनी में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो लोग कातून के खिलाफ़ इस किस्म की कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ़ कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही करेंगे ?

इस के अलावा जैसा मंत्री जी ने बताया कि घेराव के वक्त से अब तक कोई कातूनी कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ़ नहीं की गई है जिन्होंने घेराव किया है । तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन लोगों के खिलाफ़ कातूनी कार्यवाही की जायगी ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने घेराव को लीड किया उन संसद सदस्य का नाम क्या है और वह किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमन्, मैं नाम बता चुका हूँ । उन का नाम जे० एम० बिस्वास है । और सारे रेल कर्मचारियों के प्रति हमारी इतनी सहानुभूति है कि मैं सब के घरों की, कोई भी गरीब आदमी है कितनी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ से हम लोगों को पूरी वाकफियत है । लेकिन उस वाकफियत के चलते उस चीज़ को मैं बढ़ाना नहीं चाहता कि जिस की जब तबियत चाही तभी गैर कातूनी कार्यवाही कर दे । यह मेरी अंतिम चेतावनी है और अगर इस के बाद कोई रेल कर्मचारी कहीं भी गलत कार्यवाही करेंगे तो उन को कातून के अनुसार सज़ा मिलेगी ।

श्री मधु लिमये: रेलवे के बड़े अफसरान को भी मिलेगी ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: They are also government servants and they will be dealt with under the law.

SHRI J. M. BISWAS: I am that member of Parliament who had to do this thing. I do not know how far it can be called gher-

so because the officer at Adra never prevented from moving about. At the very outset we had told him "we shall be at your door; you can have your food; your movement is not restricted". On the 25th February the new United Front Government was going to take their oath of office. On the 24th of February, on the plea that the casual labour did not cast their votes for the Congress, 1,300 people were removed by the Divisional Superintendent. At that time I was on my way to Delhi. I can prove it from the reservation chart. But people forced me to get down. And I did not do it in my capacity as a member of a political party. I am the Vice-Chairman of the All India Railwaymen's Federation and the Vice-President of the South Eastern Railwayman's union. I am a born Railwayman and I have worked for the railway men for the last 22 years
(*interruptions*)

SHRI KARTIK ORAON: He is misrepresenting facts.....(*interruptions*)

MR. SPEAKER : Order, order.

SHRI J. M. BISWAS : Sir, the House should know the position.

MR. SPEAKER : It knows it already ... (*Interruptions*).

SHRI J. M. BISWAS : Sir, I want your protection. I should be given the facility to speak before this house(*Interruptions*).

SHRI S. M. BANERJEE: I was all along thinking that insanity is a disqualification for membership of this House. But, after seeing the behaviour of Shri Oraon I am convinced that insanity is not a disqualification for membership of this House.

SHRI J. M. BISWAS : Because my name has been mentioned, I have to explain my position. On the plea that they did not vote for the Congress, these 1,300 men of Adra Division who were casual labourers were removed. He was also saying: last month was the voting month; so I did not remove them; this month I have removed the n.... ..(*Interruptions*)

Even then, the Divisional Superintendent was allowed to take his food and go anywhere he liked; people were waiting outside the chamber and they were shouting slogans. Does it mean gherao ?

MR. SPEAKER : We will now take up the Calling Attention Notice.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Before that, shall I clarify one thing ? Two points have been raised; by Shri Biswas in his speech. One is that they had voted against the Congress and, therefore, the casual workers were dismissed. That is absolutely incorrect. They had participated in the 19th September strike and, therefore, the law had taken its own course. Secondly, he referred to being office-bearer of an organisation which he has named. Since they are unrecognised organisations under the rules the General Manager has nothing to do with those office-bearers.

SHRI J. M. BISWAS : The Minister is completely incorrect. Not a single casual labour at Adra was removed in connection with the 19th September strike. Not a single casual labour at Adra was removed for taking part in strike. He does not know what he is talking. He is misinformed.

DR. RAM SUBHAG SINGH : This is not the general manager that you want to gherao, Hold your tongue ... (*Interruption*). It is not the Divisional Superintendent's office. You will have to be dealt with ... (*Interruption*). From now onwards you will not be allowed to see anybody(*Interruption*).

MR. SPEAKER : Order, order.

श्री शिव नारायण : बनर्जी उस मंत्री को मुक्का दिखाते हैं यह क्या बात है ?

श्री प्रेमचन्द बर्मा : यह बेहूदा हरकतें बन्द करवाई जायें

श्री रणधीर सिंह : हम ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

MR. SPEAKER : Order, order. Will you kindly sit down now, all of you ? I know, Shri Biswas was a bit excited but Shri Oraon is always excited. Both of them are excited. What to do now ? I know that Shri Biswas was little excited. But did you not hear the noise this side ? Doing this, showing a mailed fist that side is a great sin but from this side it is not a sin ! If I could not control Shri Biswas, could I control Shri Oraon ? Both of them were shouting and if anybody could control Shri Oraon. I could also tell Shri Biswas that he was wrong. But I was a silent spectator; I was a helpless witness. Unfortunate things are happening here. Every minute he is getting up and shouting. What can I do ? To whom could I look on this side who will control the hon. Member ? Absolutely none. I am a helpless spectator.

SHRI H. N. MUKERJEE : Ministers are expected to behave with some restraint..... (Interruption).

SHRI RANDHIR SINGH : That hon. Member must behave.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Official Team's visit to U. S. A. for Purchase of Fertilizers

*721. DR. SUSHILA NAYAR :
SHRI A. SREEDHARAN :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1490 on the 29th July, 1968 and state :

(a) whether the report submitted by the official team which visited U. S. A. and other countries for the purchase of fertilizers has since been considered; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the decisions taken on the important recommendations made by the official team is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-503/69].

Export of Castor Oil

*722. SHRI M. SUDARSANAM : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the price at which Castor Oil is being exported;

(b) whether Brazil and China are offering severe competition; and

(c) if so, the price at which these two countries are underquoting vis-a-vis Indian castor oil ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The average F. O. B. value of Castor Oil exported during April-December, 1968 works out to Rs. 2,760 per tonne.

(b) Yes, Sir.

(c) The latest available prices of Castor Oil in London Market have been :

Indian Origin (Commercial)	£ 141 per Ton
Brazilian Origin (No. 1)	£ 120 per Ton
Chinese Origin	£ 119 per Ton

Aid to Nepal

*725. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total amount of aid India has given to Nepal since 1966-67; and

(b) the projects that are completed or are under progress in Nepal which are financed by India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) the total amount of aid allocated for Nepal since 1966-67 is approximately Rs. 29 crores.

(b) A list of projects completed or